भारत सरकार
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा

अतारां कत प्रश्न सं0 **2491**
दिनांक 0**8** जुलाई**,** 2019

घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन में गरावट

2491. डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः
श्री गरीश भालचन्द्र बापटः
डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शंदेः

क्या पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या घरेलू प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कमी आई है और इसकी खपत में वृ द्ध हुई है;
(ख) यदि हां, तो घरेलू प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कमी आने के पीछे क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने कच्चे तेल के आयात को कम करने, पेट्रो लयम उत्पादों के आयात को बढ़ाने और इस क्षेत्र में रोजगार सृजन करने हेतु पंचवर्षीय कार्ययोजना तैयार की है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार का अगले वर्ष तक सभी घरों में स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लए अपने लक्ष्य का नवीनीकरण करने का वचार है; और
(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा अगले वर्ष तक सभी घरों में स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्रदन करने के मशन को पूर्ण करने के लए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
पेट्रो लयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) और (ख) पछले तीन वर्षों के लए प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन और खपत म लयन मीट्रिक मानक घन मीटर (एमएमएससीएम) में निम्नानुसार है:

	2016-17	2017-18	2018-19
सकल घरेलू उत्पादन	31,897	32,649	32,873
निवल उत्पादन (ज्वलन और हानि का निवल) (क)	30,848	31,731	32056
एलएनजी आयात (ख)	24,849	27,439	28692
खपत (क+ख)	55,697	59,170	60,748

(ग) और (घ) तेल और गैस के आयात पर निर्भरता में कमी करने का लक्ष्य हा सल करने के लए मंत्रालय इस मामले में केंद्र सरकार के व भन्न मंत्रालयों के सहयोग से काम कर रहा है। इस संबंध में, पंच उद्देश्यीय कार्यनीति में मोटे तौर पर तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण संबंधी उपायों को बढ़ावा देना,मांग प्रतिस्थापन पर जोर देना, जैव ईंधनों तथा अन्य वैकल्पिक ईंधनों/नवीकरणीय ईंधनों की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करना तथा रिफाइनरी प्र क्रया में सुधारों के लए उपायों को कार्यान्वित करना आदि शा मल हैं।

सरकार ने देश में तेल और गैस का अन्वेषण और उत्पादन बढ़ाने के लए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी नीति, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसें संग नीति, उत्पादन हिस्सेदारी सं वदाओं की अव ध बढ़ाने के लए नीति, कोल बैड मथेन से शीघ्र मुद्रा अर्जित करने के लए नीति, तलछटीय बे सन में गैर मूल्यां कत क्षेत्रों का मूल्यांकन, तेल और गैस के लए व र्धत निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देना आदि शा मल हैं।

सरकार ने अन्वेषण कार्यकलाप बढ़ाने, तलछटीय बे सनों के गैर-अन्वे षत/गैर-आबंटित क्षेत्रों में घरेलू और वदेशी निवेश आक र्षत करने और मौजूदा क्षेत्रों से तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से फरवरी, 2019 में अन्वेषण और लाइसें संग नीति में प्रमुख सुधारों को अनुमोदित कर दिया है। नीतिगत सुधारों का लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ कार्य योजना को और ज्यादा प्राथ मकता देते हुए अन्वेषण कार्यकलापों को बढ़ाना, राजकोषीय और सं वदागत शर्तों को सरल बनाना, सरकार के साथ बगैर कसी उत्पादन अथवा राजस्व हिस्सेदारी के श्रेणी 2 और 3 के तलछटीय बे सनों के संबंध में अन्वेषण ब्लॉकों की बोली, राजकोषीय प्रोत्साहन दे कर खोजों से शीघ्र मुद्रा अर्जितय करना, वपणन और मूल्य निर्धारण की आजादी सहित गैस उत्पादन को प्रोत्साहित करना आदि शा मल हैं।

सरकार देश में नगर गैस वतरण (सीजीडी) नेटवर्क की कवरेज बढ़ाकर पर्यावरण के अनुकूल परिवहन ईंधन अर्थात सीएनजी के उपयोग को भी बढ़ावा दे रही है। सरकार ने एथेनॉल म श्रत पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम तथा डीजल में जैव डीजल के मश्रण के जरिए एथेनॉल और जैव डीजल जैसे वैकल्पिक ईंधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक पहलें भी की हैं। सरकार ने संपी.डत बायो गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 01.10.2018 को कफायती परिवहन के लए दीर्घका लक वकल्प (सतत) की शुरूआत की है। सरकार ने देश में जैव ईंधनों की उपलब्धता बढ़ाने के लए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 तैयार की है।

(ड.) और (च) वर्तमान में ऐसे गरीब परिवारों को प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत कनेक्शन प्रदान कया जाता है जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है बशर्ते क वे योजना की शर्तें पूरी करते हों। अभी तक पीएमयूवाई के तहत 8 करोड़ कनेक्शनों के लक्ष्य की तुलना में 7.30 करोड़ से अ धक कनेक्शन गरीब परिवारों को उपलब्ध करवाए गए हैं।

***